RAJYA SABHA

Wednesday, the 27th November, 1991/ 6 *Agrahayana,* 1913 *(Saka)*

The House met at Eleven of the Clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उग्रवाद से निपटने के लिए केंद्रीय कमान की स्थापना

81. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उग्रवाद के मामलों से निपटने और विभिन्न राज्यों में उग्रवाद से निपटने वाली एजेंसियों को दिशा निर्देश देने के लिए एक केन्द्रीय कमान की स्थापना की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम लाल राही) : (क) और (ख) यद्यपि उग्रवाद के मामलों से निपटने के लिए केन्द्रीय कमान गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद से निपटने की दृष्टि से समन्वित कार्रवाई शुरू की जा रही है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, उग्रवाद के मामलों से निपटने और विभिन्न राज्यों में उग्रवाद से निपटने वाली एजेंसियों को दिशा-निर्देश देने के लिए एक केन्द्रीय कमान की स्थापना की जा रही है कि नहीं, इस संबंध में उत्तर राज्य सभा के नेता और गृह मंत्रीजी की उपस्थित में डिप्टी होम मिनिस्टर साहब ने दिया है । जहां तक मेरी जानकारी है, डिप्टी होम मिनिस्टर साहब के जिम्मे केवल पेंशन का काम है. . .

श्री सभापति : पेंशन की दरख्वास्त देनी है आपने ?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : और मंत्री महोदय स्वयं यहां उपस्थित हैं, यह प्रश्न बड़ा गंभीर है और मेरी आपके माध्यम से सारे सदन की ओर से मंत्री महोदय से प्रार्थना होगी कि इस प्रश्न का उत्तर वे स्वयं दें ताकि देश दिशा-निर्देश उग्रवाद के मामले में प्राप्त कर सके । मैं विश्वास करता हूं कि वह मेरे आग्रह को स्वीकार कर लेंगे । मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है, उसमें नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र की बात की गयी है कि उग्रवाद से निपटने की दृष्टि से समन्वित कार्यवाही शुरू की जा रही है। सभापति महोदय, उग्रवाद या टैरेरिज्म इस देश के लिए नया शब्द नहीं है । सन् 1974-75 से उग्रवाद की शुरूआत हुई है, चाहे वह पंजाब का उग्रवाद हो, चाहे काश्मीर का उग्रवाद हो, चाहे उल्फा के माध्यम से हो, चाहे नागालैंड मिलीटेंट फोर्स के माध्यम से हो. . .

श्री सभापति : प्रश्न कर लो ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: चाहे नार्थ ईस्ट स्टेट्स के माध्यम से हो और चाहे एल टी टी ई के माध्यम से हो । इनके इलावा और भी बहुत से लोग सिर उठा रहे हैं । इसके पीछे निश्चित रूप से विदेशी ताकतों का हाथ है, यह बात कई बार सदन में बतायी गयी है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस समय कौन-कौन से प्रदेश उग्रवाद या उसके जो पर्यायी शब्द हो सकते हैं, उनकी गति-विधियों से प्रभावित हैं और क्या यह सही है कि उग्रवाद से निपटने के लिए केन्द्र को ऐसी कमान स्थापित करने के लिए आगे मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि कुछ प्रादेशिक सरकारें उग्रवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में पूर्णतः असफल सिद्ध हुई हैं । क्या केन्द्रीय कमान की स्थापना का विचार नक्सलवाद और सारे उग्रवाद के लिए जितनी भी परिभाषाएं उग्रवाद की हो सकती हैं, सब के लिए हैं और क्या राज्यों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल किए जाएंगे मान्यवर, इस बारे में

बहुत दिनों से सदन में आश्वासन दिया जा रहा है कि उग्रवाद से निपटने के लिए केन्द्रीय कमान बनायी जाएगी, तो उसमें क्या प्रगति हुई है और अंतिम निर्णय कब तक आप ले रहे हैं और उसका क्या रूप होगा, उस पर मंत्री महोदय कृपया प्रकाश डालें।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): There is no proposal for establishing a central command. This is merely a coordinated action plan which, in fact, is contemplated in areas which were affected by the Naxalite activities. Four States have been badly ties and those are Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa and Andhra Pradesh. These are the States for which a coordinated and integrated approach has been taken. In other areas, it is the respective State Governments who are supposed to take action in the matter.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : सभापति महोदय, यहां तक प्रांतीय सरकारों के यहां उग्रवाद अपना सिर उठा चुका है और प्रशासन को भी एक तरह से अनएफेक्टिव; अप्रभावशाली कर चुका है, उसका असर नहीं है और आपको सेनाएं भी भेजनी पड़ रही हैं उग्रवाद को कंट्रोल करने के लिए; चाहे वह अलफा के लोग हों, चाहे एल०टी टी०ई० के लोग हों, चाहे पंजाब में लोग हों तो क्या उत्तर प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में, आंध्र में, या मध्यप्रदेश में, बिहार में, जितने भी ऐसे प्रांत हैं, वहां के लिए भी क्या सरकार कोई विचार कर रही है ? जैसी कि आपने कोई इस तरह के एक्शन प्लान की बात की, उसे आप किस तरह से एकरूपता के साथ करेंगे ताकि विदेशी ताकतें अपना खेल खेलने में और देश में खून-खराबा करके देश में अस्थिरता फैलाने में सफल न हो सके ? और, उग्रवाद से प्रभावित लोगों को राज्य-सरकार उचित मुआवजा दे, इस पर सरकार क्या कर रही है और उसकी क्या एकरूपता बनाई गई है ? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

SHRI S. B. CHAVAN; Sir, as in the case of Naxalite-affected areas, we have set up a coordination committee and an integrated approach is being undertaken for those respective areas, Government will have to con. sider—we have not yet come to any such conclusion—that if such a situation were to arise that in integrated approach even for tackling the problem of terrorism in different States has to be taken, the respective State Governments would have to co-operate with the Central Government, although there should be no harm in setting up a coordination committee for tackling the problem of terrorism. also.

SHRI YASHWANT SINHA: I am sure the Minister must be aware that one of the reasons for growth of extremism in most parts of the country is the problem in relation to land. In many of these areas, land records are not properly maintained. Land rights which belong to the people have been taken over or usurped by the Strong men in the village and, therefore, it appears to me that one of the major thrusts in the whole strategy should be land reforms and proper maintenance of land records. I would like to know from the hon: Minister whether the Government of India is thinking in these terms and is going to issue directions to the States or help them overcome this problem.

SHRI S. B. CHAVAN: In the context of Naxalite activities all the State Governments were invited for the meeting where we have emphasised both the aspects; one is poverty alleviation programme which has. to reach the targeted group and one of the important aspect of poverty alleviation programme is also the land reforms. I am in full agreement with the hon. Member when he says that land records have not been properly maintained and there are a number of *benami* transactions also wherein people themselves see that huge chunks of land are being held by cer-

tain people while in the land records, they do not reflect the correct position and that has become a sore point for the poorer sections. That is also one aspect which in fact is responsible for creating this kind of discontent among different areas, and that is why we have to make a two-pronged attack; one will be to see that poverty alleviation programme reaches the targeted group and then we can deal with these extremist elements in a very firm manner.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब हमारे मुल्क में पापुलेशन बढ़ने लगी तो हमने हैल्थ एण्ड फमिलीं वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाई, जब शिक्षा पर गौर दिया तो हमने ह्युमेन रिसोर्सेज डवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई। परन्तु, जो होम-मिनिस्ट्री वर्ष 1950 में, 1952 में बनी थी, उसका वही ढांचा अब तक चल रहा है, जबकि हमारे देश में आतंकवाद, अलगाववाद बढ़ रहा है दिन-प्रति-दिन। तो क्या गृह मंत्रालय इसके लिए कोई एक सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट करने पर विचार कर रहा है ?

श्री सभापति : टेरेरिस्ट मिनिस्ट्री ?

SHRI S. S. AHLUWALIA; It is a whole-time job, Sir. क्योंकि पूरा नार्थ-ईस्ट और साऊथ में तमिलनाडु की जो घटनाएं घट रही हैं, हमने देखा है कि गृह मंत्रालय में...

श्री सभापति : आपका सवाल ठीक है, वे समझ गए हैं।

वे आपसे यही पूछ रहे हैं कि आप इसके लिए कुछ अलग करने वाले हैं क्या ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मेरे को कुछ नजर नहीं आता है कि ये कुछ कर रहे हैं। मेरे को यही समझ में आता है कि जो आदमी गृह मंत्री या गृह सचिव बनता है, उसे घेरे में लेने के लिए "ब्लैक कैट" जरूर खड़ी हो जाती है। अभी पंजाब, कश्मीर या उत्तर-पूर्व में असम में जो अलगाववाद की हवा चल रही है, उसमें निपटने के लिए कोई स्पेशल सैल हो। सैल में कितने आदमी मारे गए और कितनों को कम्पनसैशन मिला, इसका ही ब्यौरा रहता है। क्या पालिसी ली गई है उसको डील करने के लिए, उस पर जरा मंत्री महोदय रोशनी डालने की कृपा करें।

SHRI S. B. CHAVAN: I think the hon. Member is taking a very pessimistic view of the entire situation. Things are not really that bad as he is trying to make out. But ultimately it is a question of the States' law and order and their powers which they are exercising. I am also presiding over the Sub-committee of the Inter-State Council where the question of Sarkaria Commission report is being discussed. If the State Governments are prepared to hand over some of their powers—in fact, it is the other way about...

SHRI S. S. AHLUWALIA: What about Jammu and Kashmir?

SHRI S. B. CHAVAN: Even about Kashmir, I don't agree with the hon. Member that things are really bad. I can give him a ray of hope. I can definitely say that Kashmr is on the path of improvement and there is no reason to get dismayed. So, don't paint a very dismal picture as if nothing is happening in this country. But I quite realise that newer methods, some innovative methods will have to be found out to give proper training to personnel which, in fact, is one of the things where the Research Wing of the Home Ministry is taking necessary steps and we will write to all the State Governments to deal with the extremist elements. Special forces will have to be prescribed for dealing with such situations.

कुमारी चंद्रिका प्रेमजी केनिया : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि रोमानिया के राजदूत जो इतने समय से कैद थे टेरेरिस्ट्स के हाथों में, वे रिहा कर दिए गए हैं ।... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: आप टेरेरिस्ट्स को बधाई दे दीजिए, वह बेहतर होगा ।

†[شری محمد افضل عرف م- افضل: آپ ٹیرورسٹس کو بدھائی دے دیجئے وہ بہتر ہوگا -- (مداخلت)]

SHRI VIREN J. SHAH: Let her put her queution. Why should she be disturbed?

सवाल पूछने में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है क्या ?...(व्यवधान)

मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी : सर, जो लोग इनको ले गए थे, उन्होंने छोड़ा। रास्ते भर में पुलिस ने नहीं पहचाना । नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पुलिस ने नहीं पहचाना। टैक्सी करके वे अपने घर पहुंचे तो पुलिस ने नहीं पहचाना ।...(व्यवधान)

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی: سر جو لوگ انکو لے گئے تھے - انہوں نے چھوڑا راستے میں پولیس نے نہیں پہچانا - نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر اترے تو پولیس نے نہیں پہچانا - ٹیکسی کرکے وہ اپنے گھر پہونچے تو پولیس نے نہیں پہچانا - ... (مداخلت) ...]

श्री सभापति : उनको पूरा सवाल तो पूछने दीजिए ।

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगी कि कमांडो ट्रेनिंग कैम्प्स पाकिस्तान की ओर से चल रहे हैं। चाहे वह कश्मीर का प्रश्न हो, चाहे पंजाब का प्रश्न हो, जो मासूम नौजवान बच्चे हैं उनको वे ट्रेनिंग कैम्प्स में ले जाते हैं और वहां पर उनको टेरेरिज्म की तालीम दी जाती है । तो मैं जानना चाहूंगी सरकार से कि कौन से कदम आपने उठाए हैं ताकि जो ट्रेनिंग कैम्प्स पाकिस्तान चला रहा है, उन पर हम रोक लगा सकें ?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की बददयानत और बदनज़र कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों पर लगी हुई है । वह नहीं चाहता कि देश मजबूत बने, भारत मजबूत बने और हम विकास के रास्ते पर आगे चलें, इसलिए वह बहुत रुकावटें पैदा कर रहा है । जितने भी डेलिगेशन आते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनसे हमारी मुलाकात होती है—चाहे वह यूरोपियन पार्लियामेंटरी डेलिगेशन हो, चाहे वह इंडो-जर्मन पार्लियामेंटरी ग्रुप हो।

जब वे पाकिस्तान जाते हैं तो उनके मन में गलतफहमी पैदा की जाती है और उनको गुमराह किया जाता है । तो क्या आपके पास ऐसी कोई पद्धति है कि जिससे हम लोगों को कश्मीर और पंजाब के बारे में सही-सही मालूमात दे सकें ? उदाहरण के तौर पर मैंने कश्मीर और पंजाब के बारे में टेलीविजन पर कार्यक्रम देखे । मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे कार्यक्रम हम इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे ताकि लोगों को कश्मीर और पंजाब जैसे मसलों के बारे में सही-सही जानकारी मिल सके ?

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, as far as the first part of the question is concerned, it is a fact. There is no denying the fact that training camps are being conducted across the border by the Pakistani Army. We have enough evidence at our disposal to sub-

stantiate this. But I do not think we can do anytning more than taking up the issue at the diplomatic level. We have been trying our level best. *(Interruptions)* Mr. Viren Shah, let me answer her question first. When the Prime Minister went to Harare, he had talks with his counter-part, the Prime Minister of Pakistan, Mr. Kawaz Sharif, and both of them agreed that the issue would have to be solved bilaterally. But I do not think this has been reflected in the field so far. Something more will have to be done. The Foreign Secretary had also gone there and impressed upon them that this is how the situation was and that we will have to correct it- We hope that the Pakistan Government will see reason and not c-eate problems on our border. As 1 said, we are trying our level best at the diplomatic level.

The second part of the question is about the kind of disinformation which the Pakistan Government is spreading in international fora. We have already taken up this issue with our Information and Broadcasting Ministry to prepare such programmes which will be more impressive and which will be heard with rapt attention. Not necessarily distorting the facts. They have been distorting the facts. We wiil not distort the facts but at least, the facts should go to them. This is what we are trying to do and we are hopeful that we will get a positive response.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Mr. Chairman, Sir, in the absence of a common, reliable, forum, whatever efforts being taken by the different State Governments to deal with the extremist problem in different parts of the country will not prove effective. In this connection, I want to point out that in my State, Assam, there are some charges made against the Chief Minister by one of his own Ministers regarding talks with ULFA. Therefore, in order to deal with the extremist problem effectively, will the Government think of having a common forum so that vested interests may not create humles in the way of tackung the problem?

SHRI S. B. CHAVAN; So far as the ULFA problem in Assam is concerned, let me make it absolutely clear. There is no question of having any talks with them so long as *the* Army operation is there. There should be an unconditional surrender. They should shun all violence. They shou.d also surrender all their arms. Only when these three conditions are fulfilled, only when its top-ranking leaders surrender, the question of talks with ULFA will arise. Whatever th$_e$ statements which some people might have given, there is no truth in them. We do not propose to talk with ULFA till these three conditions are fulfilled.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : चेयरमैन महोदय, पिछले 10–12 सालों से हम टैररिज्म का बढ़ता हुआ असर देख रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सेंट्रल कमांड बनाकर टैररिज्म का मुकाबला करने के बजाय क्या हम कोई ऐसे प्रिवेंटिव मैजर्स के बारे में भी सोच रहे हैं जिससे टैररिज्म या इस किस्म की मिलिटेंट मूवमेंटज को बढ़ावा न मिल सके—

Effective sealing of international border;

priority to be given for tackling such movements at early stages;

relationship with neighbouring countries and removing the problem of unemployment.

महोदय, टैररिज्म सिर्फ एक लॉ एंड आर्डर प्रॉब्लम नहीं है।

श्री सभापति : आपका प्रश्न हो गया कि क्या इन चीजों के लिए भी कुछ कर रहे हैं ?

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : जी हां, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस किस्म के प्रिवेंटिव मैजर्स की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है ?

SHRI S. B. CHAVAN: I fully agree with the hon. Member that it is not merely a question of law and order, we will have to tackle this issue in a very delicate manner, probing deep into the matter, trying exactly to know the grievances of those who are indulging into this kind of a terrorist activity. But at the same time, I would like to bring to the notice of the hon. Members that there ' are certain countries which are interested in creating this kind of unrest ' in our country. That does not mean that we should totally give up the idea of going deep into the matter and trying to assuage the feelings of those who are, now resorting to this kind of activity. In fact, they are misled people and we should try to solve their problem.

SHRI HARVENDRA SINGH HANS-PAL: What about effectively sealing of the international border?

SHRI S. B. CHAVAN; International border sealing also we have tried our level best but having sealed the bonder in a particular area they sneak away from, the other area, that I cannot deny.

श्री कृष्ण लाल शर्मा: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जो दो समस्याएं हैं आतंकवाद की और नक्सलवाद की और मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इन दोनों चीजों के लिए एक कोऑर्डिनेटेड प्लान की बात कही है तो क्या कोई ज्वाइंट कोऑर्डिनेटेड कमेटी मिनिस्ट्री लेवल पर या इन सारी स्टेट्स के लेवल पर बनी है जो ज्वाइंट ऐक्शन प्लान के फौलो-अप को देख रही है और अगर वह देख रही है तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं?

SHRI S. B. CHAVAN: This Coordination Committee for Naxalite activity has been set up. All the four State Governments have given the names of their representatives. They have met at Hyderabad. They have prepared the Action Plan and they have also proposed as to on what lines all the State Governments should take a coordinated action, but so far as the terrorist element is concerned, this kind of a coordinated action has not been taken up by the respective State Governments. If they were to agree, certainly this will have to be considered at that time.

Clearance for Super Thermal Power Project

*82. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state;

(a) what are the norms prescribed for issuing clearance for setting up of industries;

'(b) whether it is a fact that the clearance for Super Thermal Power Project at Mangalore, which is a joint venture with USSR, is being delayed resulting in escalation of Project cost; and

(c) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The project proponents are required to provide relevant information pertaining to the likely environmental impacts of their activities in and around the sites proposed for siting of industries. The pre-requisites for consideration and issuance of clearance include the following:

(i) Filled—in questionnarie on environmental aspects;

(ii) Environmental Impacts Assessment Report along with Environmental Management Plan; and

(iii) No objection Certificate from concerned Pollution Control Board.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.